(ग) छठी योजना अवधि के दौरान जहां कहीं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होगा शेष 139 ब्लाक मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना है। फिर भी, टेलीफोन एक्सचेंजों का खोलना अर्थ की व्यवहार्यता और व्यक्तिगत टेलीफोन कनैक्शनों की मांग पर आधारित होगा।

डी० डी० ए० के० समरूप दिल्ली में एक आवास बोर्ड का गठन

2648. श्री फूलचन्द्र वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के समकक्ष एक दूसरा आवास बोर्ड गठित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास विचारार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कब तक इस तरह का बोर्ड गठित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने आरम्भ में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आवास बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया था जिसको उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था।

Central Aid for Land Reforms in Orissa

2649. SHRI RASABEHARI BEHERA: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state the amount of financial assistance given by the Central Government to Orissa State during the year 1980-81 so far for implementing the land reform schemes in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): A sum of Rs. 6,05,799 has been released to the Government of Orissa during the financial year 1980-81 as Central share under the centrally sponsored scheme of financial assistance to assignees of ceiling-surplus land.

पंचायत समितियों तथा जिला बोर्डों को सुदृढ़ बनाना

2650. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि पंचायत समितियां, गांव पंचायतें और जिला बोर्डों जैसे स्वायत्त-शासी निकायों को मजबूत बनाया जाए और पंचायत राज शक्तियों और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम हो;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की गई थी और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय पंचायतें आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं और वे प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकती और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट अगस्त, 1978 में प्रस्तुत कर दी गई थी। समिति की सिफारिशों पर मई, 1979 में हुए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था तथा उन पर सर्वसम्मति हो गयी थी। अब एक आदर्श विधान तैयार किया जा रहा है।

(ग) अधिकांश पंचायतें सुदृढ़ हैं। चूंकि पंचायती राज राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है अतः जो पंचायतें सुदृढ़ नहीं हैं, उन के संसाधनों में वृद्धि करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।

Integrated Development of Small and Medium Towns

2651. SHRI N. E. HORO:
SHRI G. Y. KRISHNAN:
SHRI CHINTAMANI JENA:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to undertake the integrated development of small and medium towns with certain population consideration;

(b) if so, the details regarding the scheme in this regard; and

(c) whether Government would also like to consider the population while investing the money in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (c). The Centrally Sponsored Scheme for Integrated Development of Small and Medium Towns having population below one lakh is under operation. The details of the Scheme are given below:—

(i) The scheme would cover towns with a population of 1 lakh and below on the basis of 1971 census.

(ii) Preference will be given to the District Headquarters of the Sub-Divisional towns or Mandi towns or other important growth centres.

(iii) The level of expenditure per town on the basis of approved schemes will be around Rs. 1 crore out of which Central loan assistance upto Rs. 40 lakhs will be released during the plan period for the schemes conforming to the guidelines, and the balance amount would be provided by the State Government and the implementing agencies.

(iv) Components eligible for assistance on a matching basis are:—

(a) Land Acquisition and Development for Residential Commercial and Industrial Schemes. Residential Scheme will include sites and services, with or without core housing.

(b) Traffic and Transportation.

(c) Development of mandis/markets, industrial estates and other service and processing facilities for benefit of agricultural and rural development in the hinterland.

(d) The State Government should include under their component schemes relating to slum improvement, urban renewal, water supply and sanitation, preventive medical facilities, parks and playground etc.

(v) It has been emphasised that local bodies of the towns should be encouraged and assisted to participate in the preparation and implementation of the programme, and also maintain the assets.

(vi) The Central assistance is provided in the form of a loan repayable in 25 years with a moratorium of 5 years at the interest rate of 5.5 per cent.

Study of Geomorphological and Environmental Study for Integrated Development Plan

2652. SHRI D. P. YADAV:
SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:

Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state: